

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 99/2018



1. बच्चू पुत्र जगन जाति जोगी निवासी ग्राम बेडा जगरामपुरा तहसील महवा जिला दौसा

...अपी०

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महवा जिला दौसा

...रेस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 22.12.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बच्चू मुकदमा नं० 312/2017 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, महवा ने दिनांक 22.12.2017 को ग्राम बेडा जगरामपुरा के आ०ख०न० 44 रकबा 0.16 है० किस्म तालाबी द्वितीय व 75 रकबा 0.09 किस्म जमीन चरागाह कुल रकबा 0.25 है० पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्प० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांत को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलांत द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांत को पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं होने पर भी पश्चातवर्ती मानकर निर्णय पारित किया है। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपीलांत के तर्कों का खंडन करते हुए बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पर उपस्थित हुआ है। अतः अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर सरसों बुआई कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया है। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

W

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी० को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामील संलग्न पत्रावली है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में सरसों बुआई कर व कौफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष सेमारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 जनवरी, 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष सेमारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

